



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166111

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 20891/2026

श्रीमती आरती और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : पूर्णिमा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण द्वारा प्रतिवादियों को पति और पत्नी के रूप में याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देते हुए परमादेश की रिट जारी किए जाने की मांग की गई है तथा संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्तागण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आगे निर्देश दिए जाने की भी मांग की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्तागण बालिग हैं और यह प्रदर्शित करने के लिए कि याचिकाकर्तागण बालिग हैं, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपनी हाई स्कूल अंकतालिका दाखिल की है, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 ने अपनी विद्यालय अंकतालिका अभिलेख पर लाई है। उन्होंने बिना किसी दबाव और अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं सहमति से विवाह संपन्न किया है तथा विवाहित दंपति के रूप में साथ रह रहे हैं। आगे यह कहा गया है कि निजी प्रतिवादी और परिवार के अन्य सदस्य नाराज हो गए हैं तथा उनके जीवन को गंभीर खतरा है क्योंकि उन्हें धमकाया और परेशान किया जा रहा है। आगे यह कहा गया है कि याचिकाकर्तागण ने अपने विवाह के पंजीकरण के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। याचिका में किए गए अभिकथनों का समर्थन याचिकाकर्तागण के संयुक्त शपथपत्रों द्वारा किया गया है।

4. याचिकाकर्तागण ने रिट याचिका में अभिकथन किया है कि वे पत्नी और पति के रूप में रह रहे हैं। यह कहा गया है कि उन्हें आशंका है कि निजी प्रतिवादी अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए उनकी हत्या कर सकता/सकती है। ऐसी स्थिति में, यदि यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उनके जीवन को खतरा हो सकता है।

5. यद्यपि निजी विरोधी पक्ष को नोटिस जारी किए गए हैं तथा इस न्यायालय के समक्ष न्यायाधीश द्वारा अंतरिम संरक्षण भी प्रदान किया गया है, लेकिन पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, केवल निजी विरोधी पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के लिए याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

6. तदनुसार, पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की सहमति से, न्यायालय के नियमों के अनुसार इस रिट याचिका का इस चरण पर अंतिम रूप से निस्तारण किया जा रहा है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. उच्चतम न्यायालय ने निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में विधि को निर्धारित किया है कि जहां एक लड़का और एक लड़की बालिग हैं और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से रह रहे हैं, तो उनके माता-पिता सहित कोई भी व्यक्ति उनके एक साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा ज्ञान देवी बनाम अधीक्षक, नारी निकेतन, दिल्ली और अन्य, (1976) 3 एससीसी 234; लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2006) 5 एससीसी 475; तथा भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396 के मामलों में दिए गए निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है, जिनका उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा निरंतर अनुसरण किया गया है, साथ ही इस न्यायालय द्वारा दीपिका और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2013 (9) एडीजे 534 में दिए गए निर्णय का भी। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञान देवी (पूर्वोक्त) में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"7. ... याचिकाकर्ता की जन्मतिथि चाहे जो भी हो, तथ्य यह है कि वर्तमान में उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। चूंकि याचिकाकर्ता स्वविधि-संपन्न है, इसलिए उस व्यक्ति के चयन पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता जिसके साथ उसे रहना है, न ही उस स्थान के संबंध में कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है जहां उसे रहना चाहिए। न्यायालय या याचिकाकर्ता के रिश्तेदार भी ऐसे मामले में याचिकाकर्ता की राय या पसंद के स्थान पर अपनी राय या पसंद प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।"

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि याचिकाकर्तागण को एक साथ रहने की स्वतंत्रता है और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किए जाने की स्थिति में, याचिकाकर्तागण इस आदेश की

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रमाणित प्रति के साथ पुलिस आयुक्त, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष उपस्थित होंगे, जो याचिकाकर्तागण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे।

9. निजी प्रतिवादी को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि अभिलेख पर लाए गए दस्तावेज कूटरचित या जाली हैं, तो उसके लिए इस आदेश को वापस लेने हेतु पुनर्विचार आवेदन दाखिल करना खुला होगा।

10. उच्चतम न्यायालय के (2006) 2 एससीसी 578 और (2008) 1 एससीसी 180 में प्रकाशित निर्णय, सीमा (श्रीमती) बनाम अश्वनी कुमार, के अनुसार विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, अतः याचिकाकर्तागण दो माह की अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराने का वचन देते हैं और यदि याचिकाकर्तागण उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करा सके, तो इस आदेश के अंतर्गत प्रदान की गई सुरक्षा स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्तागण के कथित विवाह का न्यायनिर्णयन नहीं किया है और यह आदेश किसी भी प्रकार उनके विवाह की वैधता के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करता है।

12. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है। खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

7 अगस्त, 2026

एस. अली

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”